हरियाणा राज्य वी. कुलदीप सिंह @ किप्पा और अन्य
(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस भारद्वाज जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य - अपीलकर्ता

बनाम

कुलदिप सिंह @किप्पा और अन्य - प्रतिवादी

2022 का सी.-आर.ए.-ए.एस. न0 22

14 मार्च, 2022

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस.एस.392, 379-बी. और 34 - राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर - बंदूक की नोक पर शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल और नकदी लूटी गई - आरोपियों के नाम ज्ञात नहीं, केवल गांव का नाम ज्ञात - शिकायतकर्ता आरोपियों की पहचान करने में विफल रहा -अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया - शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया - अभियोजन उचित संदेह की छाया से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहा - बरी करने का फैसला - राज्य की अपील खारिज - ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई अवैधता, अनुचितता या विकृति नहीं, अपीलीय अदालत आम तौर पर फैसले को रद्द नहीं करेगी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के बारे में मतभेद के आधार पर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों पर कानूनी स्थिति का सारांश दिया गया।

माना गया कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से तय किए गए कानून के अवलोकन से जो स्थिति सामने आती है, उसे निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

i) आपराधिक अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां समान रूप से व्यापक हैं, चाहे अपील दोषसिद्धि के खिलाफ हो या दोषमुक्ति के खिलाफ।

ii) बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने में, उच्च न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है कि निर्दोषता की धारणा मजबूत होती है।

iii) एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय आम तौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा होता है, खासकर जब उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित होता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को आचरण को देखने का लाभ होता है जिन गवाहों ने गवाही दी है.

iv) बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण" हों।

v) अपीलीय अदालत को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी करने के फैसले को रद्द नहीं करना चाहिए जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, भले ही अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण अधिक संभावित हो सकता है।

vi) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में, अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान 'भाषा के पनपने' की प्रकृति में अधिक हैं।

vii) अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा या बाहर करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री पर विचार करके निकाले गए हैं। निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के वजन के विरुद्ध" है, या यदि निष्कर्ष इतनी अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दोष से ग्रस्त है।

इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपीलीय अदालत आम तौर पर ट्रायल कोर्ट से अपनी राय के अंतर के आधार पर दोषसिद्धि के फैसले को तब तक रद्द नहीं करेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट की राय अवैधता, विकृति से ग्रस्त न हो। साक्ष्य की दुर्बलता या घोर गलत मूल्यांकन। मेरी राय है कि उक्त मामले में प्रतिवादी-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देने और उन्हें आरोपमुक्त करने में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधता, अनुचितता या विकृति नहीं है।

अपीलकर्ता की ओर से कंवर संजीव कुमार, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

विनोद एस. भारद्वाज, जे.

(1) वर्तमान अपील धारा 392 और 379-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 75 दिनांक 16.08.2017 पुलिस थाना रोरी जिला सिरसा में आई.पी.सी. के मामले में 2017 के सीआईएस संख्या 223- एससी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 के खिलाफ दायर की गई है।

मामले के तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

i. मैं दिनांक 16.08.2017 को शिकायतकर्ता रमेश कुमार पुत्र माखन लाल ने पुलिस को एक आवेदन देकर आरोप लगाया कि जब वह रात लगभग 11/11:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था। दिनांक 15.08.2017 को वह ट्यूबवेल की मोटर ठीक करके गुरदेव सिंह पुत्र मोहन सिंह के घर के पास पहुंचा ही था कि दो लड़कों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली। वे पिस्तौल और डंडा से लैस थे. पिस्तौल से लैस लड़के ने उसके कंधे पर पिस्तौल तान दी और मोटरसाइकिल छोड़ने को कहा। डंडा से लैस दूसरे लड़के ने उसकी जेब से 14500 रुपये निकाल लिये. इसके बाद वे शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। उक्त दोनों लड़के चेहरे से उसे जानते थे लेकिन वह उनका नाम नहीं बता सका। वे मट्टर गांव के रहने वाले थे. पूछताछ करने पर उक्त लड़कों का नाम किपा सिंह

पुत्र नत्था सिंह तथा बग्गी पुत्र नछत्तर सिंह दोनों मजबी सिख बताया गया। संबंधित एफआईआर तदनुसार दर्ज की गई थी।

ii. मामले में उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी किपा सिंह उर्फ कुलदीप से 7500/- रुपये और आरोपी बग्गी उर्फ मंगत राम से 7000/- रुपये की राशि के साथ पूछताछ में मोटरसाइकिल बरामद की गई। पिस्तौल और डंडा, जिसका कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया था, को भी कब्जे में ले लिया गया।

iii. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए पांच गवाहों से पूछताछ की। हालाँकि, यह बताना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता ने पीडब्लू-1 के रूप में उपस्थित होते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। शिकायतकर्ता उन आरोपियों के उत्तरदाताओं की पहचान करने में विफल रहा, जिन्होंने उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी। सरकारी वकील के अनुरोध पर पीडब्लू-2 जग्गा सिंह को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

iv. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद, अभियुक्तों का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया और सभी आपत्तिजनक साक्ष्य उनके सामने रखे गए, जिन पर उन्होंने निर्दोष होने और

गलत फंसाने की दलील दी। हालाँकि उनके द्वारा बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

v. प्रतिस्पर्धी पक्षों द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने पाया कि आईपीसी की धारा 379बी के साथ धारा 34 के साथ पढ़ी गई एफआईआर मोटरसाइकिल के साथ-साथ 14,500 रुपये दो लड़कों द्वारा जबरन छीनने के आरोप में दर्ज की गई थी। जिन्हें शिकायतकर्ता पहचान सकता था लेकिन जिनके नाम ज्ञात नहीं थे।

शिकायतकर्ता ने पीडब्लू-1 और गवाह पीडब्लू-2 के रूप में उपस्थित होते हुए कहा है कि प्रतिवादी-अभियुक्त वे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने अपराध किया था और वे उन्हें अपराध करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानने में विफल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने हमलावरों को पहचानने का दावा किया था। उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने में विफल रहा और इस प्रकार उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

(2) श्री कंवर संजीव कुमार, विद्वान राज्य वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा के फैसले पर जोरदार तर्क देकर हमला किया है कि प्रतिवादी-अभियुक्त व्यक्तियों से

मोटरसाइकिल की वसूली के साथ-साथ 14,500/- रुपये की राशि भी प्रभावित हुई है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन मोटरसाइकिल शिकायतकर्ता की है। इसलिए, उत्तरदाताओं के प्रकटीकरण के आधार पर वसूली के रूप में परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने उत्तरदाताओं-आरोपी व्यक्तियों के साथ अपराध के संबंध को विधिवत स्थापित किया।

(3) मैंने विद्वान राज्य वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से तत्काल मामले के तथ्यों और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ा है।

(4) अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान पर आधारित था। शिकायतकर्ता द्वारा विशेष रूप से कहा गया था कि दो व्यक्तियों, जिन्हें शिकायतकर्ता पहचान सकता था लेकिन जिनके नाम ज्ञात नहीं थे, ने शिकायतकर्ता से मोटरसाइकिल के साथ-साथ 14,500/- रुपये की राशि भी छीन ली थी। बाद में शिकायतकर्ता द्वारा हमलावरों के नाम बताए गए, जिससे उत्तरदाताओं की गिरफ्तारी हुई। शिकायतकर्ता और पीडब्लू-2 जग्गा सिंह ने हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि मुकदमे का सामना कर रहे उत्तरदाता वे हमलावर नहीं थे जिन्होंने मोटरसाइकिल के साथ-साथ नकदी भी छीन ली थी। आगे, जहां तक 14,500/- रुपये की वसूली का सवाल है, इसे उत्तरदाताओं को अपराध के कमीशन से जोड़ने के लिए वसूली के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। करेंसी नोटों की पहचान साबित करने के लिए नोटों की विशिष्ट विशेषता वाले नंबरों

का उल्लेख करना होगा। निश्चित रूप से, मुद्रा के मूल्यवर्ग या मुद्रा संख्या का कोई विवरण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता है कि उत्तरदाताओं से बरामद मुद्रा वास्तव में मुद्रा नोट थे जो उनके कब्जे से छीन लिए गए थे। शिकायतकर्ता।

(5) इस प्रकार मोटरसाइकिल की बरामदगी हो जाती है। विचाराधीन अपराध मोटरसाइकिल को जबरन छीनने के कारण किया गया था। उत्तरदाताओं-अभियुक्तों की पहचान को स्वयं हमलावर नहीं होने से इनकार किया गया है, जिन परिस्थितियों में मोटरसाइकिल उत्तरदाताओं के कब्जे में आई, उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया जाना था और इस तरह का बोझ आरोपी पर नहीं डाला जा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले से यह भी पता नहीं चल रहा है कि मोटरसाइकिल की बरामदगी किसी ऐसे स्थान से की गई थी जो विशेष रूप से उत्तरदाताओं की जानकारी में थी और इसे सार्वजनिक दृष्टिकोण से छुपाया गया था। इसके अलावा, उक्त बरामदगी को अंजाम देने में पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया है।

(6) यह साबित करने का दबाव कि उत्तरदाताओं-अभियुक्तों ने वास्तव में अपराध किया था, अभियोजन पक्ष राज्य पर था और आईपीसी की धारा 392 और 379-बी के तहत अपराध के होने को केवल कथित रूप से छीनी गई मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर नहीं माना जा सकता है। चोरी/छीनी गई संपत्ति के कब्जे में होने से वास्तव में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने

वास्तव में आईपीसी की धारा 392 और 379-बी के तहत दंडनीय अपराध किया था। उत्तरदाताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 411 के तहत अपराध के लिए कोई आरोप नहीं है और भले ही इसे आजमाए गए अपराधों का कम आरोप नहीं कहा जा सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। एक मात्र वसूली, जो किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित और पुष्ट नहीं है, जो यह दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों से वसूली प्रभावित हुई थी, वे वास्तव में वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध किया था, उन व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त होगा। मुकदमे का सामना करने तक. अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को उचित संदेह की छाया से परे साबित करने का दायित्व है। किसी आरोपी को संभावनाओं की प्रबलता या यहां तक कि गंभीर संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि संदेह, चाहे कितना भी गंभीर हो, मामले को साबित करने की आवश्यकता का विकल्प नहीं है। पुनर्प्राप्ति, सर्वोत्तम स्थिति में, एक संदिग्ध परिस्थिति है।

एक बार जब शिकायतकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं-अभियुक्तों की पहचान से विशेष रूप से इनकार कर दिया जाता है, भले ही उसने अपनी एफआईआर में दावा किया हो कि वह उन हमलावरों की पहचान करने में सक्षम होगा जिन्होंने उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी, तो उसका बयान महत्वपूर्ण हो जाता है।

<u>बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में कानूनी स्थिति</u>

(7) इससे अब बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पैदा हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एम.जी. अग्रवाल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** के मामले में जो व्यवस्था दी है, उसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है:

"(16) धारा 423(1) अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को उसके समक्ष प्रस्तुत अपीलों के निपटान में निर्धारित करती है और खंड (ए) और (बी) क्रमशः दोषमुक्ति के खिलाफ अपील और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील से निपटते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति, जो दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित है, खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति जितनी ही व्यापक है, जो दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित है, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि आपराधिक अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ समान रूप से व्यापक हैं, चाहे विचाराधीन अपील दोषमुक्ति के विरुद्ध हो या दोषसिद्धि के विरुद्ध। यह प्रश्न का एक पहलू है। प्रश्न का दूसरा पहलू उस दृष्टिकोण पर केंद्रित है जिसे उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के लिए अपनाता है। ऐसी अपीलों से निपटने में, उच्च न्यायालय स्वाभाविक रूप से आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को ध्यान में रखता है और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि उक्त धारणा ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके पक्ष में पारित बरी के आदेश से मजबूत होती है। और इसलिए, यह तथ्य कि आरोपी व्यक्ति उचित संदेह के लाभ का हकदार है, उच्च न्यायालय के दिमाग में हमेशा

मौजूद रहेगा जब वह मामले के गुणों पर विचार करेगा। एक अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय आम तौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा होता है, खासकर जब उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित होता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को गवाहों के आचरण पर नजर रखने का लाभ होता है। सबूत दे दिया है. इस प्रकार, हालांकि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां उतनी ही व्यापक हैं जितनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील से निपटने में, अपीलों के पूर्व वर्ग से निपटने में, इसका दृष्टिकोण सर्वोपरि विचार द्वारा नियंत्रित होता है। निर्दोषता के अनुमान से बह रहा है। कभी-कभी, शक्ति की चौड़ाई पर जोर दिया जाता है, जबकि अन्य अवसरों पर, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील से निपटने में सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, और यह जोर समय-समय पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों या वाक्यांशों में व्यक्त किया जाता है। लेकिन वास्तविक कानूनी स्थिति यह है कि बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कितना भी सतर्क और सतर्क क्यों न हो, वह निस्संदेह अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध या बेगुनाही के संबंध में पेश किए गए सबूतों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार है। अभियुक्त। यह स्थिति प्रिवी काउंसिल द्वारा शेओ स्वरूप बनाम द किंग एम्परर और नूर मोहम्मद बनाम एम्परर एआईआर 1945 पीसी 151 में स्पष्ट की गई है।

(17) हालाँकि, इस न्यायालय के पहले के कुछ निर्णयों में, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील से निपटने में सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए, यह देखा गया कि निर्दोषता की धारणा को बरी करने के आदेश से प्रबलित किया जाता है और इसलिए, " ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष, जिसमें गवाहों को देखने और उनके साक्ष्यों को सुनने का लाभ था, को केवल बहुत ठोस और सम्मोहक कारणों से उलटा किया जा सकता है": सूरजपाल सिंह बनाम राज्य के मामले में इसी तरह अजमेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, यह देखा गया कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण हों।') कुछ अन्य निर्णयों में, यह कहा गया है कि बरी करने के आदेश को उलटा किया जा सकता है केवल "अच्छे और पर्याप्त रूप से ठोस कारणों" या "मजबूत कारणों" के लिए। इन टिप्पणियों के प्रभाव की सराहना करते समय, यह याद रखना चाहिए कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक कठोर या अनम्य नियम बनाना नहीं था जो उच्च के निर्णय को नियंत्रित करे। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में न्यायालय। उनका उद्देश्य संहिता की धारा 423 (1) के खंड (ए) में एक अतिरिक्त शर्त पेश करना नहीं था, और ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। उक्त सभी टिप्पणियों का इस बात पर जोर देने का इरादा है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सतर्क होना चाहिए क्योंकि जैसा कि लॉर्ड रसेल ने शेओ स्वरूप के मामले में देखा था, निर्दोषता का अनुमान इसके पक्ष में है। आरोपी "नहीं है

निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर हो गया है कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है।" इसलिए, अभिव्यक्ति "पर्याप्त और सम्मोहक कारणों" द्वारा सुझाए गए परीक्षण को एक सूत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जिसे हर मामले में कठोरता से लागू करना होगा। यही प्रभाव है इस न्यायालय के हाल के निर्णयों में, उदाहरण के लिए, सांवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य और हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य में; और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि बरी करने के फैसले को उलटने से पहले, उच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से चरित्र-चित्रण करना चाहिए उसमें दर्ज निष्कर्ष विकृत हैं। इसलिए, वर्तमान अपीलों में हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन का मामला साबित हो गया है। उचित संदेह से परे, और ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण गलत था। इस प्रश्न का उत्तर देने में, हम निस्संदेह साक्ष्य की मुख्य और व्यापक विशेषताओं पर विचार करेंगे ताकि की गई शिकायत की सराहना की जा सके। अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के विरुद्ध। लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत हम आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होंगे, खासकर जहां उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित हों।

(8) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नागभूषण** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] के मामले में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"7.2 योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने से पहले, दोषमुक्ति के खिलाफ अपील पर कानून और धारा 378 सीआरपीसी का दायरा और दायरा। और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर विचार करना आवश्यक है।

बाबू बनाम केरल राज्य (2010) 9 एससीसी 189 के मामले में, इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया था। पैराग्राफ 12 से 19 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना जाता है:

12. इस न्यायालय ने बार-बार ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और बरी के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय अदालत को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी करने के फैसले को रद्द नहीं करना चाहिए जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, हालांकि अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण अधिक संभावित हो सकता है। बरी करने के फैसले से निपटने के दौरान, अपीलीय अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि ट्रायल कोर्ट के विचार विकृत थे या अन्यथा टिकाऊ नहीं थे। अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या किसी तथ्य पर पहुंचने में ट्रायल कोर्ट स्वीकार्य साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा है और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों पर विचार किया है। इसी प्रकार, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी अपीलीय अदालत द्वारा जांच का विषय हो सकता है। (वीडियो बालक राम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एससीसी 219, शंभू मिसिर बनाम

बिहार राज्य (1990) 4 एससीसी 17, शैलेन्द्र प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 1 एससीसी 761, नरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2004) 10 एससीसी 699, बुद्ध सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2006) 9 एससीसी 731, स्टेट ऑफ यूपी। बनाम राम वीर सिंह (2007) 13 एससीसी 102, एस. राम बनाम एस. रामी रेड्डी (2008) 5 एससीसी 535, अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एससीसी 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम राज्य ए.पी. (2009) 16 एससीसी 98 और राम सिंह बनाम एच.पी. राज्य। (2010) 2 एससीसी 445)

13. शेओ स्वरूप बनाम किंग एम्परर एआईआर 1934 पीसी 227 में, प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार कहा: (आईए पृष्ठ 404) "... उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों पर उचित महत्व और विचार करना चाहिए और विचार करना चाहिए (1) विचार गवाहों की विश्वसनीयता के संबंध में ट्रायल जज की; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा, एक धारणा निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं हुई है कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में अपीलीय अदालत की सुस्ती, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था।

14. कानून के उपरोक्त सिद्धांत का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है। (देखें तुलसीराम कानू बनाम राज्य एआईआर 1954 एससी 1, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1957 एससी 216, एमजी अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1963 एससी 200, खेदू मोहटन बनाम बिहार राज्य

(1970) 2 एससीसी 450, सांबसिवन बनाम केरल राज्य (1998) 5 एससीसी 412, भगवान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) 4 एससीसी 85 और गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान (2007) 3 एससीसी 755).

15. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415 में, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार दोहराया: (एससीसीपी 432, पैरा 42) "(1) एक अपीलीय अदालत के पास समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है साक्ष्य जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है।

(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय अदालत तथ्य और कानून दोनों के सवालों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर विचार कर सकती है।

(2) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान 'भाषा के पनपने' की प्रकृति में अधिक हैं।

(3) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी

धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, आरोपी ने अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली है, उसकी बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी मजबूत, पुन: पुष्टि और मजबूत किया गया है।

(4) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष **में बाधा नहीं डालनी चाहिए** ।

16. घूरे लाल बनाम यूपी राज्य (2008) 10 एससीसी 450 में, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराया, यह देखते हुए कि अपीलीय अदालत को उन मामलों से निपटने में जिनमें ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के बरी होने से इस धारणा को बल मिलता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित महत्व और विचार देना चाहिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट को गवाहों के आचरण को देखने का विशिष्ट लाभ था, और वह बेहतर स्थिति में थी।

गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें।

17. राजस्थान राज्य बनाम नरेश (2009) 9 एससीसी 368 में, न्यायालय ने फिर से इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की जांच की और निर्धारित किया कि: (एससीसी पृष्ठ 374, पैरा 20) "20। ... बरी करने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं

किया जाना चाहिए, भले ही अदालत को लगे कि कुछ सबूत आरोपी की ओर इशारा कर रहे हैं।''

18. यूपी राज्य में बनाम बन्ने (2009) 4 एससीसी 271, इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ दीं जिनमें न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित होगा। परिस्थितियों में शामिल हैं: (एससीसी पृष्ठ 286, पैरा 28)"(i) उच्च न्यायालय का निर्णय स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

(ii) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और दस्तावेजों के विपरीत हैं;

(iii) सबूतों से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर हानि हुई;

(iv) मामले के रिकॉर्ड पर गलत कानून और तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है;

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

(vi) यह न्यायालय ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने में बेहद अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज किया हो। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा धनपाल बनाम राज्य (2009) 10 एससीसी 401 में दोहराया गया है।

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी परिस्थितियां हैं, और अपील के तहत निर्णय विकृत पाया जाता है, अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है। अपीलीय अदालत को अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को ध्यान में रखना चाहिए और आगे यह कि ट्रायल कोर्ट का बरी होना उसकी बेगुनाही की धारणा को मजबूत करता है। जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो वहां नियमित तरीके से हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।'' (जोर दिया गया)

जब किसी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है, तो उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में इस पर विचार किया गया है, जो इस प्रकार है:

“20. किसी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा या बाहर करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री पर विचार करके निकाले गए हों। निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के वजन के विरुद्ध" है, या यदि निष्कर्ष इतनी अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दोष से ग्रस्त है। (**वाईड** राजिंदर कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन (1984) 4 एससीसी 635, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर-कम-असेसिंग अथॉरिटी बनाम गोपी नाथ एंड संस 1992 सप्लिमेंट (2) एससीसी 312, त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम सीसीई 1994 सप्लिमेंट। (3) एससीसी 665, गया दीन बनाम हनुमान प्रसाद (2001) 1 एससीसी 501,

अरुवेलु बनाम राज्य (2009) 10 एससीसी 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2009) 10 एससीसी 636)। (जोर दिया गया)

कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त (1999) 2 एससीसी 10 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद, यह देखा गया है कि यदि कोई निर्णय बिना किसी सबूत या पूरी तरह से अविश्वसनीय सबूत और बिना किसी उचित **कारण के व्यकित** इस पर कार्य करेगा, आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड पर कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

7.3 विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एससीसी 436 के मामले में, इस न्यायालय के पास फिर से सीआरपीसी की धारा 378 के दायरे पर विचार करने का अवसर था। और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। इस न्यायालय ने 1952 से ही इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। अनुच्छेद 31 में, इसे निम्नानुसार देखा और रखा गया है:

“31. उम्मेदभाई जादवभाई (1978) 1 एससीसी 228 मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों की पुनः सराहना पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया था। रिकॉर्ड पर। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलटते हुए, आरोपी को बरी

करते समय निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा: (एससीसी पृष्ठ 233) "10। एक बार जब बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से पूरे सबूतों की फिर से सराहना करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश की राय को उचित महत्व देगा यदि वह साक्ष्य की उचित सराहना के बाद तय की गई हो। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

31.1 संबासिवन बनाम कराला राज्य (1998) 5 एससीसी 412 में, उच्च न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया और रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना पर आरोपी को दोषी ठहराया, हालांकि, उच्च न्यायालय इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या सबूतों से निपटने में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने का आदेश विकृत था और कमजोरियों से ग्रस्त था, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए,

इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 416) "

8. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपील के तहत फैसले का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबुला दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996) 9 एससीसी 225 अर्थात इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से आगे नहीं बढ़ाया है। पहले इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या सबूतों से निपटने में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा, हालांकि उच्च न्यायालय ने एक प्रतिपादन किया है। अच्छी तरह से विचार किया गया निर्णय इसके समक्ष उठाए गए सभी विवादों को विधिवत पूरा करता है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन अपील के तहत फैसले को रद्द करने को उचित ठहराएगा? हम सोचते हैं, नहीं. हमारे विचार में, ऐसे मामले में, अदालत का दृष्टिकोण, जो एक अपीलीय अदालत के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को पलट दिया है, खुद को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि ट्रायल **कोर्ट** का दृष्टिकोण सबूतों से निपटने में अदालत स्पष्ट रूप से अवैध थी या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अस्थिर थे और क्या अपीलीय अदालत का निर्णय उन कमजोरियों से मुक्त था; यदि ऐसा है तो यह माना जाए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को परेशान किया

जाए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं है, तो यह नहीं माना जा सकता कि बरी करने के आदेश में अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द करना होगा क्योंकि दो उचित विचारों में से, केवल बरी करने के समर्थन में ही खड़ा होना होगा। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम कराला राज्य (1999) 3 एससीसी 309 में, यह देखने के बाद कि हालांकि आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ दम है कि उच्च न्यायालय ने दिए गए सभी कारणों पर ध्यान नहीं दिया है। ट्रायल जज द्वारा बरी करने के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि बरी करने के आदेश को दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और निष्कर्ष निकाला गया विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर दिया गया निर्णय टिकाऊ नहीं था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करना उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय साक्ष्यों की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष को दर्ज करने का पूरी तरह से हकदार था। इस न्यायालय ने चश्मदीदों के साक्ष्यों की जांच की और राय दी कि चश्मदीदों की गवाही को खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने

यह भी देखा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

एटली बनाम यूपी राज्य में। एआईआर 1955 एससी 807, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया और आयोजित किया: (एआईआर पृ. 809-10)

"5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला दोषमुक्ति का है, इसलिए उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए सबूतों की सराहना के आधार पर इसे तब तक रद्द नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता। कि ट्रायल जज का निर्णय विकृत था। हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत सीआरपीसी की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी करने का निर्णय विकृत था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती थी।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और निश्चित रूप से, अच्छी तरह से स्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला है। अभियुक्तों की बेगुनाही की धारणा कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी के फैसले से मजबूत हुई है, जिसमें उन गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था जिनके साक्ष्य उसकी उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील की अदालत के पास दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील में सबूतों की सराहना करने की उतनी ही व्यापक शक्तियाँ हैं जितनी कि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, शर्तों के अधीन जिसके साथ निर्दोषता का अनुमान लगाया जाता है। आरोपी व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में शुरू होता है और अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने बरी करने का आदेश दर्ज किया था।

यदि अपीलीय अदालत उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करती है, और विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय ख़राब हो गया है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम राज्य एआईआर 1952 एससी 52; विलायत खान बनाम यूपी राज्य एआईआर 1953 एससी 122) हमारी राय में, उठाए गए विवाद में कोई दम नहीं है अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों की समीक्षा करना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आना उचित नहीं था।

के. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य (1979) 1 एससीसी 355 में, इस न्यायालय ने देखा है कि जहां ट्रायल कोर्ट खुद को काल्पनिक संदेहों से घिरा होने की अनुमति देता है, मामूली कारणों से विश्वसनीय सबूतों को खारिज कर देता है और उन सबूतों पर विचार करता है जो लेकिन मुश्किल से ही संभव है, न्याय के हित में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है, ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन का उपहास उड़ाया जाए। (जोर दिया गया)

(9) इस प्रकार, बरी किए जाने के खिलाफ अपील से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से तय किए गए कानून के अध्ययन से जो स्थिति सामने आती है, उसे निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

i) आपराधिक अपीलों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां समान रूप से व्यापक हैं, चाहे अपील दोषसिद्धि के खिलाफ हो या दोषमुक्ति के खिलाफ।

ii) बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने में, उच्च न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है कि निर्दोषता की धारणा मजबूत होती है।

iii) एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय आम तौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को **बाधित** करने में धीमा होता है, खासकर जब उक्त निष्कर्ष मौखिक साक्ष्य की सराहना पर आधारित होता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट को आचरण को देखने का लाभ होता है जिन गवाहों ने गवाही दी है.

iv) बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब "ऐसा करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण" हों।

v) अपीलीय अदालत को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी करने के फैसले को रद्द नहीं करना चाहिए जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं, भले ही अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण अधिक संभावित हो सकता है।

vi) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में, अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान 'भाषा के पनपने' की प्रकृति में अधिक हैं।

vii) अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा या बाहर करके या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री पर विचार करके निकाले गए हैं। निष्कर्ष को विकृत भी कहा जा सकता है यदि यह "साक्ष्य के वजन के विरुद्ध" है, या यदि निष्कर्ष इतनी अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि तर्कहीनता के दोष से ग्रस्त है।

निष्कर्ष:

(10) इसलिए यह अच्छी तरह से तय है कि अपीलीय अदालत आम तौर पर ट्रायल कोर्ट से अपनी राय के अंतर के आधार पर दोषसिद्धि के फैसले को तब तक रद्द नहीं करेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट की राय अवैधता, विकृति, दुर्बलता या साक्ष्य की घोर गलत सराहना से ग्रस्त न हो। मेरी राय है कि उक्त मामले में प्रतिवादी-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देने और उन्हें आरोपमुक्त करने में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधता, अनुचितता या विकृति नहीं है।

(11) तदनुसार वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा के फैसले की पुष्टि की जाती है।

शुब्रीत कौर

अस्वीकरणः—स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक व अधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

संगीता, अनुवादक, सोनीपत।